

Q1. भारतीय संविधान के किस भाग में आपात काल का उपबंध किया गया है?

- (A) भाग 15 (B) भाग 16
(C) भाग 17 (D) भाग 18

Q2. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

- a. आंतरिक अशांति
b. सशस्त्र विद्रोह
c. बाह्य आक्रमण
d. युद्ध

उपर्युक्त में से किस आधार पर अनु 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है-

- (A) a, b और c (B) b, c, और 4
(C) a, c और 4 (D) a, b और 4

Q3. निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बंध में की जा सकती है?

- (A) 42 वां संविधान संशोधन
(B) 44 वां संविधान संशोधन
(C) 51 वां संविधान संशोधन
(D) 56 वां संविधान संशोधन

Q4. 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था?

- (A) ज्ञानी जैल सिंह
(B) नीलम संजीव रेड्डी
(C) फखरुद्दीन अली अहमद
(D) शंकर दयाल शर्मा

Q5. राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा, कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है?

- (A) 14 दिन (B) 30 दिन
(C) 60 दिन (D) 90 दिन

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है।
2. राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है।

उपर्युक्त में सत्य है-

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) दोनों असत्य हैं।

Q7. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है, कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे।
2. संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
3. संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है।

कूट-

- (A) 1 और 2
(B) 2 और 3
(C) तीनों कथन सत्य हैं।
(D) तीनों कथन असत्य हैं।

Q8. संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है?

- (A) 1 माह (B) 3 माह
(C) 6 माह (D) 1 वर्ष

Q9. राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है?

- (A) अनु 355 (B) अनु 356
(C) अनु 357 (D) अनु 358

Q10. आपात काल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है?

- (A) अनु 358 (B) अनु 359
(C) A और B दोनों (D) इनमें से कोई नहीं।

Q11. किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
2. राष्ट्रपति सम्बंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है।

उपर्युक्त में सत्य है-

- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) दोनों असत्य हैं।

Q12. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है?

- (A) 6 माह (B) 1 वर्ष
(C) 2 वर्ष (D) 3 वर्ष

Q13. भारत में वित्तीय आपात काल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है?

- (A) 1 बार (B) 2 बार
(C) 3 बार (D) एक बार भी नहीं

Q14. निम्नलिखित में कौन सी समिति केंद्र राज्य सम्बन्ध से सम्बंधित नहीं है?

- (A) राजमन्नार समिति (B) सरकारिया आयोग
(C) तारकुंडे समिति (D) पूँछी आयोग

Q15. निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए?

- (A) वेंकटचेलैया समिति
(B) सरकारिया आयोग
(C) आनंदपुर साहिब प्रस्ताव
(D) राजमन्नार समिति

Q16. पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?

- (A) बलवंत राय मेहता (B) पी.के. थुंगन
(C) अशोक मेहता (D) डॉ. पी. वी. के. राव

Q17. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ ?

- (A) 24 अप्रैल 1992
(B) 24 अप्रैल 1993
(C) 20 अप्रैल 1992
(D) 20 अप्रैल 1993

Q18. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?

- (A) 74 वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संविधानिक दर्जा दिया गया।
(B) किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्रामसभा कहा जाता है।
(C) ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है।
(D) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है।

Q19. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?

- (A) अनुच्छेद 243 K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
(B) राज निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
(C) पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है।
(D) पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

Q20. यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात् गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिये कार्य करेगी ?

- (A) गठन के पश्चात् 5 साल तक
(B) 6 माह तक
(C) शेष अवधि तक
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q21. एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए ?

- (A) 50% (B) 33 %
(C) 27% (D) 22%

Q22. एक पंचायत के भंग होने के..... माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा ?

- (A) 3 माह (B) 6 माह
(C) 12 माह (D) 1 माह

Q23. किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है

- (A) राज्य का राज्यपाल (B) राज्य का मुख्यमंत्री
(C) राष्ट्रपति (D) गृहमंत्री

Q24. 12वी अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है?

- (A) 18 विषय (B) 28 विषय
(C) 12 विषय (D) 11 विषय

Q25. भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ?

- (A) कलकत्ता में (B) मद्रास में
(C) पटना में (D) अजमेर में

Q26. किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया ?

- (A) 96 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
(B) 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
(C) 98 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
(D) 99वें संविधान संशोधन द्वारा

Q27. निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए?

- (A) गाडगिल समिति
(B) राजमन्नार समिति
(C) पी.के. थुंगन समिति
(D) लक्ष्मीमल सिंघवी समिति

Q28. संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है ?

- (A) भाग 9(ख) (B) भाग 14(क)
(C) भाग 15 (D) भाग 19

Q29. राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है ?

- (A) विधानसभा सभा चुनाव संपन्न कराना
(B) विधान परिषद चुनाव संपन्न कराना
(C) ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q30. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?

- (A) 1 मई, 1950 (B) 14 नवंबर, 1951
(C) 2 अक्टूबर, 1952 (D) 2 जनवरी, 1956

Q31. राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?

- (A) गोविंद बल्लभ पंत द्वारा
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा
(C) पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
(D) डॉ. जोगेंद्र मंडल द्वारा

Q32. उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके/किनके द्वारा किया जा सकता है?

- (A) संसद द्वारा
(B) राज्य विधान मंडल द्वारा
(C) A और B दोनों द्वारा
(D) उच्चतम न्यायालय द्वारा

Q33. उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है?

- (A) स्पेशल लीव पिटिशन
(B) जनहित याचिका
(C) पुनर्विचार याचिका
(D) रिट याचिका

Q34. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?

- (A) उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति- अनुच्छेद 143
(B) तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति - अनुच्छेद 131
(C) कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक- अनुच्छेद 108
(D) उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना - अनुच्छेद 64

Q35. राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में किसके परामर्श से करेगा?

- (A) राज्य के महाधिवक्ता
(B) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) राज्यपाल
(D) इनमें से कोई नहीं

Q36. भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था?

- (A) प्रिवी काउंसिल
(B) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
(C) संघीय न्यायालय
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q37. यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा?

- (A) प्रधानमंत्री
(B) मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश

Q38. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है-

- स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना
- विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा ना पहुंचाना
- सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना
- न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना

कूट:

- (A) केवल 1, 2 और 4
(B) केवल 1 और 4
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

Q39. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं-

- मौलिक क्षेत्राधिकार
- अपीलीय क्षेत्राधिकार
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार
- रिट संबंधी क्षेत्राधिकार

कूट:

- (A) केवल 1 और 4
- (B) केवल 1, 3 और 4
- (C) केवल 1, 2 और 4
- (D) उपर्युक्त सभी

Q40. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे?

- (A) एम हिदायतुल्ला
- (B) ए एस आनंद
- (C) ए एम अहमदी
- (D) पी एन भगवती

Q41. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) उपराष्ट्रपति
- (C) राज्यपाल
- (D) लोकसभा अध्यक्ष

Q42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

A. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया।

B. जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।

उपर्युक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कूट:

- (A) केवल A
- (B) केवल B
- (C) A और B
- (D) न ही A और न ही B

Q43. भारत में 'मोबाइल कोर्ट' को किसके मानसपुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है?

- (A) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
- (B) डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- (C) एम हिदायतुल्लाह
- (D) इनमें से कोई नहीं

Q44. निम्नलिखित न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए-

- (A) कोलकाता हाईकोर्ट- पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार
- (B) केरल हाईकोर्ट- केरल और लक्षद्वीप
- (C) मुंबई हाईकोर्ट- महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
- (D) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

Q45. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए-

- (A) वह भारत का नागरिक हो।
- (B) भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो।
- (C) एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- (D) B तथा C दोनों

Q46. किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई?

- (A) 14 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा
- (B) 15 संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा
- (C) 14 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा
- (D) 15 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा

Q47. किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा?

- (A) अनुच्छेद 215
- (B) अनुच्छेद 216
- (C) अनुच्छेद 127
- (D) अनुच्छेद 129

Q48. भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
3. संविधान का अनुच्छेद - 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है

उपर्युक्त में से सही कथन हैं -

- (A) 1 और 2
- (B) 2 और 3
- (C) 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q49. भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिये-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करना
 2. निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना
 3. राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना
- उपर्युक्त में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाते हैं -

- (A) 1 और 2
(B) 2 और 3
(C) 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q50. संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है -

- (A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) गृहमंत्री
(D) संसद

Q51. संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है -

- (A) संसद के आदेश पर
(B) राज्यसभा के प्रस्ताव पर
(C) राज्यपाल के अनुरोध पर
(D) कभी नहीं

Q52. निम्नलिखित में से किसे 'मेरिट पद्धति का प्रहरी' माना गया है -

- (A) संसद
(B) सर्वोच्च न्यायालय
(C) संघ लोक सेवा आयोग
(D) केंद्रीय सतर्कता आयोग

Q53. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है -

- (A) राज्यपाल
(B) राज्य विधानसभा
(C) राष्ट्रपति
(D) मुख्यमंत्री

Q54. वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिये -

1. इसका वर्णन संविधान के अनु. - 280 में किया गया है
 2. यह एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है
 3. इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है
- उपर्युक्त में से सही कथन हैं -

- (A) 1 और 2
(B) 2 और 3
(C) 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q55. प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे -

- (A) के. सी. नियोगी
(B) के. संथानम
(C) पी. वी. राजमन्नार
(D) सी. रंगराजन

Q56. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया -

- (A) 86 वां
(B) 89 वां
(C) 92वां
(D) 97 वां

Q57. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है -

- (A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) लोकसभा
(D) लोक लेखा समिति

Q58. भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है -

- (A) इसका वर्णन संविधान के अनु. 76 में किया गया है
(B) इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
(C) यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है
(D) इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है

Q59. नीति आयोग है, एक -

- (A) संवैधानिक निकाय
(B) वैधानिक निकाय
(C) गैर - संवैधानिक निकाय
(D) इनमें से कोई नहीं

Q60. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है -

- (A) मूल संविधान में
(B) संविधान संशोधन के द्वारा
(C) संसद द्वारा पारित अधिनियम से
(D) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर

TEST-01

Q61. मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है -

- (A) 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक
- (B) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
- (C) 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक
- (D) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

Q62. केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था -

- (A) 1964 में
- (B) 1976 में
- (C) 1993 में
- (D) 1999 में

Q63. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं?

- (A) अनुच्छेद 6 से 11
- (B) अनुच्छेद 6 से 12
- (C) अनुच्छेद 5 से 12
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q64. निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं?

1. लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार
2. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
3. विधि के समक्ष समता

विकल्प -

- (A) 1,2
- (B) 1,3
- (C) 2,3
- (D) 1,2,3

Q65. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है।
2. भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?

विकल्प -

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q66. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ?

- (A) शोषण के विरुद्ध अधिकार - अनुच्छेद 23-24
- (B) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार - अनुच्छेद 29 - 30
- (C) स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19 - 22
- (D) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 26- 28

Q67. निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है?

- (A) अधिकार पृच्छा
- (B) उत्प्रेषण
- (C) प्रतिषेध
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q68. निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है?

- (A) जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत हो।
- (B) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान
- (C) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान
- (D) राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान

Q69. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

1. अनुच्छेद 34- मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति
2. अनुच्छेद 33-मार्शल ला
3. अनुच्छेद 35 - मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

विकल्प -

- (A) 1,2
- (B) 2,3
- (C) 1,3
- (D) 1,2,3

Q70. भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में ' संपत्ति के अधिकार' की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी?

- (A) 19 (1) (घ)
- (B) 19(1) (ड.)
- (C) 19(1)(छ)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q71. भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

- (A) कनाडा
- (B) रूस
- (C) ब्रिटेन
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q72. भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है?

- (A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 32
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q73. निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

- (A) अनुच्छेद 41- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
(B) अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं संबंधी उपबंध
(C) अनुच्छेद 43(क)- कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी
(D) अनुच्छेद 43(ख)- सहकारी समितियों की अभिवृद्धि

Q74. नीति निदेशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है?

- (A) यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में विस्तृत है।
(B) इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है।
(C) नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है।
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q75. निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

- (A) अनुच्छेद 43B- सहकारी समितियों की अभिवृद्धि
(B) अनुच्छेद 48A - राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
(C) अनुच्छेद 39A - सामान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता
(D) अनुच्छेद 47 - स्वास्थ्य के लिए नुकसान देह नशीली दवाओं, मदिरा ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध

Q76. 'समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता' उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 39-a) किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया ?

- (A) 25 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(B) 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(C) 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(D) 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम

Q77. बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को के कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है।

- (A) 2 माह
(B) 3 माह
(C) 4 माह
(D) 6 माह

Q78. सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई है?

- (A) 101
(B) 102
(C) 103
(D) 104

Q79. संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?

- (A) भाग 9
(B) भाग 10
(C) भाग 11
(D) भाग 12

Q80. किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है?

- (A) 42वें संविधान संशोधन
(B) 44 वां संविधान संशोधन
(C) 76 वां संविधान संशोधन
(D) 86 वां संविधान संशोधन

Q81. समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है?

- (A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति

Q82. केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जाँच एवम् बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद् का गठन कौन करता है?

- (A) संसद
(B) प्रधानमंत्री
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) राष्ट्रपति

Q83. केंद्र एवम् राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है?

- (A) वित्त मंत्रालय
(B) वित्त आयोग
(C) आरबीआई
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय

Q84. आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का सम्बन्ध किससे है?

- (A) वित्त मामलों से
(B) न्यायिक व्यवस्था सुधार से
(C) केंद्र राज्य सम्बंधों से
(D) पंचायतों से

Q85. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है?

- (A) राष्ट्रपति
- (B) सम्बंधित राज्य विधानमंडल आपसी सहमति से
- (C) संसद
- (D) राज्यपाल

Q86. भारतीय संसद द्वारा बनाये गए कानून लागू होंगे?

- (A) भारतीय क्षेत्र के अंदर
- (B) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर
- (C) विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर
- (D) उपर्युक्त सभी पर

Q87. प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?

- (A) एम्.सी.शीतलवाड़
- (B) मोरारजी देसाई
- (C) मदनमोहन मुंछी
- (D) आर.एस. सरकारिया

Q88. यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारन्टी देती है तो ये गारन्टी किस पर भारित होगी?

- (A) राज्य की संचित निधि पर
- (B) केंद्र की संचित निधि पर
- (C) आरबीआई पर
- (D) इनमे से कोई नहीं

Q89. संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक सम्बंधों की व्याख्या की गई है?

- (A) अनुच्छेद 245 से 255 तक
- (B) अनुच्छेद 256 से 263 तक
- (C) अनुच्छेद 264 से 267 तक
- (D) अनुच्छेद 268 से 293 तक

Q90. समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी?

- (A) 1980
- (B) 1984
- (C) 1992
- (D) 1996

Q91. निम्न में कौन सा राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है?

- (A) आम आदमी पार्टी
- (B) नेशनल पीपुल्स पार्टी
- (C) राष्ट्रवादी कांग्रेस
- (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

Q92. किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप मान्यता पाने के लिए निम्न में कौन सी दशा पूरी करनी होती है?

- (A) कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता
- (B) कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता
- (C) चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8 प्रतिशत मत
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q93. देश में सन् 2019 में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे?

- (A) पन्द्रहवें
- (B) सोलहवें
- (C) सत्रहवें
- (D) अठारहवें

Q94. निम्न कथनों पर विचार कीजिए –

1. राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
2. राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा /से कथन सत्य नहीं है -

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 व 2
- (C) केवल 2
- (D) न तो 1, न तो 2

Q95. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है -

- (A) राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
- (B) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
- (C) राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
- (D) राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है।

Q96. सुमेलित नहीं है –

अनुच्छेद - वर्णित उपबंध

- (A) 153 – प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल
- (B) 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
- (C) 213 – राज्यपाल का अभिभाषण
- (D) 174 – विधानसभा का विघटन

Q97. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है -

- (A) भारतीय संविधान में सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है।
- (B) भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है।
- (C) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
- (D) राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची है।

Q98. राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए -

1. वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
2. वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है।
3. वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिता रखता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है -

- (A) केवल 1
(B) केवल 1, 2
(C) 1, 2, 3
(D) केवल 1 व 3

Q99. यदि किसी राज्य में विधानपरिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है -

- (A) ¼ सदस्यों को
(B) 1/5 सदस्यों को
(C) 1/6 सदस्यों को
(D) 1/12 सदस्यों को

Q100. किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों (मूल कर्तव्यों) को भारतीय संविधान में जोड़ा गया ?

- (A) 28 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(B) 32 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(C) 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम
(D) 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम

Q101. सुमेलित नहीं है -

अनुच्छेद - वर्णित उपबंध

- (A) 52 - भारत का राष्ट्रपति
(B) 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति
(C) 54 - राष्ट्रपति की पदावधि
(D) 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया

Q102. राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं -

- (A) राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य
(B) दिल्ली व पाण्डिचेरी विधानसभाओं के सदस्य
(C) दिल्ली, पाण्डिचेरी, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(D) उपर्युक्त सभी

Q103. राष्ट्रपति से संबंधित निम्नकथनों पर विचार करें -

1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
2. राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
3. भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है -

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) उपर्युक्त सभी

Q104. निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है-

- (A) माता - पिता अथवा अभिभावक अपने 8-14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।
(B) भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें।
(C) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।
(D) देश की रक्षा करें और आहुवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

Q105. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा, जब वह -

1. भारत का नागरिक हो।
2. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. लाभ का पद धारण नहीं करता हो।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर कौन सा /से कथन असत्य है -

- (A) केवल 2
(B) केवल 3
(C) केवल 2 व 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q106. राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है -

- (A) इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
(B) एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल का पदभार (पद का कार्यभार) ले सकता है।
(C) जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता, वह अपने पद पर कार्य करता रहेगा।
(D) राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है।

Q107. किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब वह -

- (A) 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(B) 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(C) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(D) आयु का निर्धारण नहीं किया गया

Q108. निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है ?

- (A) महान्यायवादी
(B) महाधिवक्ता
(C) महालेखा परीक्षक
(D) राजभाषा आयोग का अध्यक्ष

Q109. निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है ?

- (A) इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया ।
- (B) इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया ।
- (C) गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया ।
- (D) भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना ।

Q110. भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

- (A) कनाडा के संविधान से
- (B) अमेरिकी संविधान से
- (C) ब्रिटेन के संविधान से
- (D) फ्रांस के संविधान से

Q111. 1 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गये थे?

- (A) 13 अनुच्छेद
- (B) 14 अनुच्छेद
- (C) 15 अनुच्छेद
- (D) 16 अनुच्छेद

Q112. भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- 1. इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी।
 - 2. इसने प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था।
 - 3. इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी।
- उपर्युक्त कथनों में सही कथन / कथनों का चुनाव करें –

- (A) 1 एवं 2
- (B) केवल 3
- (C) उपर्युक्त सभी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q113. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?

- (A) एन. गोपालास्वामी
- (B) जवाहर लाल नेहरू
- (C) अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
- (D) के. एम. मुंशी

Q114. निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे?

- 1. ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया।
- 2. सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ।
- 3. कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को कर दिया गया।

कूट :

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 एवं 2
- (D) 1, 2 एवं 3

Q115. संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है?

- (A) प्रांतीय संविधान समिति – जे. बी. कृपलानी
- (B) प्रारूप समिति – डॉ. भीमराव अंबेडकर
- (C) संचालन समिति – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (D) सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति – एस. वरदाचारी

Q116. निम्नलिखित में से यह किसका कथन था – ‘उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है।’

- (A) न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह
- (B) डॉ. भीमराव अंबेडकर
- (C) के. एम. मुंशी
- (D) सुभाष कश्यप

Q117. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को ‘हितैषी निरंकुशवाद’ का नाम दिया गया?

- (A) भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
- (B) भारत शासन अधिनियम, 1919
- (C) भारत शासन अधिनियम, 1935
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Q118. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था?

- (A) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
- (B) चार्टर एक्ट, 1813
- (C) चार्टर एक्ट, 1833
- (D) चार्टर एक्ट, 1853

Q119. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है।

2. संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से सही कथन/कथनों का चुनाव करें

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 एवं 2
(D) न तो 1 और न ही 2

Q120. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है ?

- (A) संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत
(B) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
(C) न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत
(D) उपर्युक्त सभी

Q121. निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है?

- (A) आपातकाल का प्रावधान
(B) केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति
(C) अखिल भारतीय सेवाएं
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान

Q122. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है?

- 1) समवर्ती सूची का प्रावधान
2) अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
3) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

विकल्प-

- (A) 1 और 2
(B) 1 और 3
(C) 2 और 3
(D) 1,2 और 3

Q123. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा/से कथन गलत है?

- 1) प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है।
2) प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है।

विकल्प-

- (A) 1
(B) 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न तो 2

Q124. विधान परिषद के विषय में सत्य कथन है/ हैं-

1- इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है।

2- विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी।

3- इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

कूट:

- (A) 1 और 2
(B) 2 और 3
(C) 1 और 3
(D) सभी सत्य है

Q125. निम्नलिखित में से कौन-कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं?

- 1- अविश्वास प्रस्ताव
2- निंदा प्रस्ताव
3- विशेषाधिकार प्रस्ताव
4- स्थगन प्रस्ताव

कूट:

- (A) 1 और 2
(B) 1, 2 और 4
(C) 1, 2 और 3
(D) सभी

Q126. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी ?

- (A) अनुच्छेद 71
(B) अनुच्छेद 72
(C) अनुच्छेद 73
(D) अनुच्छेद 74

Q127. प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है ?

- (A) प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
(B) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
(C) वह बहुमत दल का नेता होता है।
(D) उपर्युक्त सभी।

Q128. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है?

- (A) 1/10
(B) 1/5
(C) 1/4
(D) 1/3

Q129. संविधान के किस अनुच्छेद में 'राज्य का महाधिवक्ता' पद का प्रावधान है?

- (A) 163
(B) 165
(C) 167
(D) 169

Q130. विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- 1- यह भारत के सभी राज्यों में है।
- 2- इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- 3- विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
- 4- राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

उपर्युक्त में सत्य नहीं है-

- (A) 1 और 3 (B) 2 और 4
(C) 1, 2, और 4 (D) 1, 2, 3 और 4

Q131. राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है?

- (A) 1 माह (B) 2 माह
(C) 3 माह (D) 4 माह

Q132. किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है?

- (A) अनुच्छेद 102 (B) अनुच्छेद 108
(C) अनुच्छेद 112 (D) अनुच्छेद 114

Q133. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?

- (A) साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता
(B) संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार
(C) चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता
(D) अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार

Q134. निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है?

- (A) बजट सत्र (B) ग्रीष्मकालीन सत्र
(C) मानसून सत्र (D) शीतकालीन सत्र

Q135. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- 1- मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है।
- 2- मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं।
- 3- मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदाई होते हैं।
- 4- मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कूट:

- (A) 1 और 2 (B) 2 और 3
(C) 1 और 3 (D) 1 और 4

Q136. निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है?

- (A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री
(C) संसद (D) प्रशासक

Q137. राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है?

- (A) वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है
(B) राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं।
(C) वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है।
(D) वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है।

Q138. निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है?

- 1- वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है।
- 2- कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है।
- 3- वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है।

दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

- (A) 1 और 2 (B) 2 और 3
(C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

Q139. संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव है-

- (A) कटौती प्रस्ताव
(B) विशेषाधिकार प्रस्ताव
(C) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(D) स्थगन प्रस्ताव

Q140. सुमेलित नहीं है ?

राज्य - लोक सभा में आवंटित सीट

- (A) राजस्थान-25
(B) पंजाब -12
(C) गोवा -2
(D) बिहार -40

व्याख्यात्मक हल

Q1.

Ans: D**Solution:**

भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात काल का प्रावधान किया गया है। जबकि, भाग 15- निर्वाचन भाग 16-कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 17 - राजभाषा से सम्बंधित है। आपात काल का उपबंध अनुच्छेद 352-360 तक में है। यह जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है।

Q2.

Ans: B**Solution:**

भारत में अनु 352 के तहत तीन आपात की घोषणा तीन आधार पर की जाती है-

- युद्ध
- वाह्य आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह

उल्लेखनीय है 44 वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

Q3.

Ans: A**Solution:**

42 वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है।

Q4. **Ans: C****Solution:**

1975 में घोषित आपात के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उल्लेखनीय है यह आपात काल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के घोषित किया था। जिसमें आगे चलकर 44 वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा, जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए।

Q5. **Ans: B****Solution:**

यदि राष्ट्रपति द्वारा घोषित उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा, 30 दिन / 1 माह के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है।

Q6. **Ans: B****Solution:**

राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। लोकसभा को भी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है।

Q7. **Ans: C****Solution:**

जब आपात काल प्रवर्तन में रहता है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार राज्यो को यह निर्देश देने तक हो जाता है, कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करें। संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है, वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि आपात की समाप्ति के बाद 6 माह बाद समाप्त हो जाती है।

Q8. **Ans: C****Solution:**

संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रहती है। आगे 6- 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

Q9. **Ans: B****Solution:**

अनु 356 के तहत राज्यो में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

Q10. **Ans: C****Solution:**

आपात काल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या पड़ता है, इसका प्रावधान संविधान के अनु 358 और 359 में बताया गया है।

Q11. Ans: A**Solution:**

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों को संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाती हैं।

लेकिन राष्ट्रपति सम्बंधित राज्य की उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता।

Q12. Ans: D**Solution:**

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है।

Q13. Ans: D**Solution:**

भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय आपात काल के विषय में प्रावधान अनु 360 में किया गया है।

Q14. Ans: C**Solution:**

तारकुंडे समिति का सम्बंध चुनाव सुधार से सम्बंधित है। जबकि विकल्प में दी गयी अन्य केंद्र राज्य सम्बन्ध से सम्बंधित है।

Q15. Ans: A**Solution:**

वेंकटचेलैया समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए।

इस समिति में , प्रधानमंत्री , गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।

Q16. Ans: A

Solution: पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन हेतु गाँव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया।

Q17. Ans: B

Solution: 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया , जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 23 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया तथा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। इस तरह 24 अप्रैल 1993 से 73वाँ संविधान

संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Q18. Ans: B

Solution: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संविधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद (B) 4(C) के अनुसार ग्राम सभा, गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करें। ग्राम पंचायत , ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है।

Q19. Ans: C

Solution: संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 K के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आयोग को पंचायतों में नगरपालिका के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण , निदेशक और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है तथा पंचायत चुनाव का निर्णय राज सरकार द्वारा किया जाता है।

Q20. Ans: C

Solution: नगर पालिका की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है उसे 5 वर्ष के पूर्व भंग किया जा सकता है, यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए इस प्रकार गठित नगरपालिका अपने शेष अवधि तक कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि यदि विघटित नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आवश्यक नहीं है।

Q21. Ans: B

Solution: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33 % पद आरक्षित होनी चाहिए।

Q22. Ans: B

Solution: पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। विघटित होने की दशा में इसके भी घटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।

Q23. Ans: A

Solution: किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है।

Q24. Ans: A

Solution: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9क शामिल किया गया , इसे 'नगरपालिकाए' नाम दिया गया। इस अधिनियम के कारण सविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं की 18कार्यकारी विषय- वस्तुओं का उल्लेख है।

Q25. Ans: B

Solution: 1687- 88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। इसके पश्चात 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए।

Q26. Ans: B

Solution:संसद ने दिसंबर 2011में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97वां संविधान संशोधन पारित किया था। यह 15 फरवरी, 2012 से लागू हुआ था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1))c में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 b और भाग 9 b को सम्मिलित किया गया।

Q27. Ans: C

Solution: 1988 मे गठित पी. के. थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 मे संविधान संसोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। परन्तु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका।

Q28. Ans: A

Solution: संविधान में जोड़े गये भाग 9(ख) में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

Q29. Ans: C

Solution: राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों में निर्वाचन संपन्न कराने का प्राधिकार विभाग होता है

Q30. Ans: C**Solution:**

सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित थे।

Q31. Ans: C**Solution:**

राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।

इस योजना का उद्घाटन दिवंगत प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले में किया था।

यह योजना बाद में 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (दिवस) भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

Q32. Ans: C

Solution: 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के संगठन संबंधी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अतः इस संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

Q33. Ans: A

Solution: उच्च न्यायालयों की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उनके निस्तारण की क्षमता कम है।

सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह बोझ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन के कारण बढ़ता है, जो किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली स्पेशल लीव पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में नित्य प्रयोग की जाने वाली एक अपरिहार्य घटना हो गई है। इसके लगभग 85% मामले लंबित है।

Q34. Ans: B

Solution: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद-127 में है। जबकि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद-131 में प्रावधान है।

Q35. Ans: B

Solution: अनुच्छेद 222 के अनुसार स्थानांतरण से पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा।

Q36. Ans: A

Solution: ब्रिटिश शासन के दौरान जिसे आमतौर पर किंग ऑफ काउंसिल या प्रिवी काउंसिल कहा जाता था, भारत में अदालतों द्वारा पारित फैसले और आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च मंच था। इसने भारतीय और अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के बीच पुल के रूप में कार्य किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कानून की व्याख्या करने और संघीय मामलों से संबंधित विवादों पर न्याय निर्णयन के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया

था।

Q37. Ans: D

Solution: भारत के राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है यदि वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाता है।

नोट: अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश एवं हिदायतुल्ला राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं।

Q38. Ans: C

Solution: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारीता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है। अतः कथन 2, 3 और 4 न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं।

Q39. Ans: D

Solution: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित आते हैं-

- ◆आरंभिक क्षेत्र अधिकार -अनुच्छेद 131
- ◆अपीलीय क्षेत्राधिकार -अनुच्छेद 132, 133 134 एवं 136
- ◆सलाहकार क्षेत्राधिकार -अनुच्छेद 143
- ◆अभिलेख न्यायालय की शक्तियां -अनुच्छेद 129
- ◆न्यायादेश क्षेत्राधिकार (रिट संबंधी)- अनुच्छेद 32
- ◆न्यायिक समीक्षा की शक्ति
- ◆अन्य शक्तियां व क्षेत्राधिकार

Q40. Ans: D

Solution: भारतीय न्यायिक व्यवस्था में PIL अर्थात जनहित वाद की शुरुआत पी एन भगवती के मुख्य न्यायाधीश काल में हुई। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अर्ह है।

Q41. Ans: A

Solution: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 (2) में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं और कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उन पर सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप सिद्ध करना पड़ता है।

Q42. Ans: C

Solution: उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। जिला न्यायाधीशों की

नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन तथा प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किया जाएगा जबकि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो और उसकी नियुक्ति की उच्च न्यायालय ने सिफारिश किया हो।

Q43. Ans: B

Solution: भारत में मोबाइल कोर्ट को डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। 4 अगस्त, 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत (Mobile court) का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (APJ Abdul Kalam) ने की थी।

Q44. Ans: C

Solution: भारत के 6 उच्च न्यायालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल तथा पंजाब एवं हरियाणा ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर है।

कोलकाता हाईकोर्ट- पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार

केरल हाईकोर्ट- केरल और लक्षद्वीप

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

कर्नाटक हाईकोर्ट- कर्नाटक

मुंबई हाईकोर्ट- महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव

Q45. Ans: B

Solution: उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 214 तथा अनुच्छेद 231 में दिया गया है। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

Q46. Ans: B

Solution: 15 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई अर्थात् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया भी जा सकता है।

Q47. Ans: A

Solution: अनुच्छेद 215 के तहत 'उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना' का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्याय मूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 129 में 'उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना' का उल्लेख किया गया है।

Q48. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर होता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Q49. Ans: D

Solution: भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में अनुच्छेद - 324 में उपबंध किया गया है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने, चुनाव की तिथि घोषित करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना आदि आयोग के प्रमुख कार्य हैं।

Q50. Ans: A

Solution: यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा अध्यक्ष अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पा रहा हो तो आयोग के सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

Q51. Ans: C

Solution: संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है जो अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराता है। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग किसी मामले पर राज्य को सुझाव दे सकता है।

Q52. Ans: C

Solution: संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है

जिसका वर्णन संविधान के भाग - 14 में (अनु. 315 - 323) किया गया है। संविधान में आशा की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग मेरिट पद्धति का प्रहरी होगा।

Q53. Ans: C

Solution: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है किंतु उनको पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। संविधान के भाग - 14 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियाँ, गठन इत्यादि का वर्णन है।

Q54. Ans: A

Solution: वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 280 में किया गया है। यह एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

Q55. Ans: A

Solution: वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले की जाती है। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में की गयी थी एवं इसके अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे।

Q56. Ans: B

Solution: 1990 के 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनु. 338 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था किंतु 89वें संशोधन 2003 के द्वारा पुनः संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़ा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक आयोग के रूप में स्थान दे दिया गया।

Q57. Ans: B

Solution: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो इसे संसद के पटल पर रखते हैं।

Q58. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान के अनु. 76 में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गयी है जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है अर्थात् राष्ट्रपति कभी भी इसे पद से हटा सकते हैं। परंपरा के अनुसार चूँकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है इसलिए जब सरकार (मंत्रिपरिषद्) इस्तीफा देती है तो इनको भी इस्तीफा देना होता है।

Q59. Ans: C

Solution: वर्ष 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त कर उस के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

Q60. Ans: C

Solution: मूल संविधान में भारतीय मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था नहीं थी। इसका गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।

Q61. Ans: B

Solution: केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गयी थी। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।

Q62. Ans: A

Solution: केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। यह देश में भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है।

Q63. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान के भाग - 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं -

1. अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
2. अनुच्छेद 6- पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (3) अनुच्छेद - 7 - पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
- (4) अनुच्छेद 8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (5) अनुच्छेद 9- विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
- (6) अनुच्छेद 10- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- (7) अनुच्छेद 11- संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

Q64. Ans: A

Solution: भारतीय संविधान केवल भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है -

1. अनुच्छेद 15 (धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार)
2. अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार)
3. अनुच्छेद 19 (वाक् स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,

सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता)

4/5 - अनुच्छेद 29 व 30 (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)

Q65. Ans: D

Solution: उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। भारत में राज्यों के लिए किसी पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है जहां प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है बल्कि वह राज्य विशेष का भी नागरिक होता है।

Q66. Ans: D

Solution: विकल्प d सही सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में विद्यमान है -

अनुच्छेद 25 - अंतः करण की और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 27- धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 28- धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।

Q67. Ans: D

Solution: उपरोक्त सभी विकल्प गलत हैं। परमादेश रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं-

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश - यह न्यायालय की एक नियंत्रणात्मक व्यवस्था है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ की जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
3. प्रतिषेध
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा

Q68. Ans: C

Solution: राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। जबकि ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी विन्यास/न्यास के तहत हो, धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या राज्य से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है।

Q69. Ans: A

Solution: अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू

करने के संबंध में संसद की शक्ति से जबकि अनुच्छेद 34 मार्शल ला के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है।

Q70. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान के भाग-3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में शामिल संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 (1)(च) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाप्त करते हुए संपत्ति के अधिकार को एक 'विधिक अधिकार' के रूप में अनुच्छेद 300(क) में रखा गया है।

Q71. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।

Q72. Ans: B

Solution: भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है जबकि देश के भीतर निर्बाध रूप से विचरण को अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है।

Q73. Ans: C

Solution: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद - 43 में है जबकि अनुच्छेद 43 (क) में 'उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना' संबंधी प्रावधान है।

Q74. Ans: D

Solution: उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान में निदेशक तत्वों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - समाजवादी, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। यद्यपि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर - न्यायोचित होती है तथापि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Q75. Ans: B

Solution: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है।

Q76. Ans: B

Solution: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निदेशक

तत्वों की मूल सूची में 4 नए तत्व जोड़े गए -

1. बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना
2. समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना
3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना
4. रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करना

Q77. Ans: B

Solution: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। पूर्व में बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को 3 माह तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया सकता था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा घटाकर 2 माह कर दिया गया है।

Q78. Ans: C

Solution: सरकारी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत की गई है जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (EWS) के लिए 10% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत की गई है।

Q79. Ans: C

Solution: संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण भाग 11 में दिया गया है। जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी सम्बन्ध, अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक सम्बन्ध, तथा 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों की चर्चा की गई है।

Q80. Ans: A

Solution: शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42 वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा 42 वें संविधान संशोधन के तहत वन, नाप तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, एवम् न्याय का प्रशासन आदि विषयों को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया था।

Q81. Ans: B

Solution: संविधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

Q82. Ans: D

Solution: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और

राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जाँच एवम् बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सदस्यों के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं।

Q83. Ans: B

Solution: केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्ति का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण करने की सिफारिस राष्ट्रपति से वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। यह एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है।

Q84. Ans: C

Solution: आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सम्बन्ध लेंडर राज्य सम्बंधों से है। ये प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई थी। इसमें कहा गया था कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश सम्बन्ध, संचार एवम् मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए एवम् संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

Q85. Ans: C

Solution: संयुक्त राज्य लोक सेवा का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद बना सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

Q86. Ans: D

Solution: संसद द्वारा बनाया गया कानून न सिर्फ भारत में रह रहे भारतीय नागरिकों एवम् विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। संसद का कानून भारतीय नागरिकों एवम् उनकी विश्व में कहीं भी स्थित संपत्ति पर लागू होता है।

Q87. Ans: B

Solution: केंद्र सरकार ने 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में केंद्र राज्य सम्बंधों को सुधारने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एम्.सी.शीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया।

Q88. Ans: B

Solution: केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार के ऋण लेने पर गारन्टी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन पर आवश्यक धनराशि केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होगी।

Q89. Ans: B

Solution: संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र

राज्य के बीच प्रशासनिक सम्बंधों की व्याख्या की गई है।

Q90. Ans: C

Solution: समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में की गई थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, तथा 1996 में राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की गई थी।

Q91. Ans: A

Solution: भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं - बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी।

Q92. Ans: A

Solution: यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है

1. कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हों।
2. कोई दल यदि 4 अलग अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाये हों और लोक सभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों।
3. किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो।

Q93. Ans: C

Solution: देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे तब से लेकर अब तक 2019 तक सत्रह आम चुनाव हो चुके हैं।

Q94. Ans: A

Solution: राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं।

Q95. Ans: D

Solution: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली (System) का संबंध न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया से है।

Q96. Ans: C

Solution: संविधान के अनुसार अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

Q97. Ans: A

Solution: केवल विकल्प A सही है।

भारतीय संविधान में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बाद राष्ट्रपति पद को धारण कर चुका है। वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अगर किसी सदन का सदस्य है तो उसे निर्वाचित होने के पश्चात् अपना पद ग्रहण के पूर्व सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। (यह मान लिया जाता है, कि उसने संसद / विधानसभा की सदस्यता अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।) राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 60 में उल्लेखित है।

Q98. Ans: C

Solution: सभी कथन सत्य है

Q99. Ans: C

Solution: यदि किसी राज्य में विधानमण्डल के साथ विधानपरिषद का भी गठन किया गया है तो राज्यपाल विधानपरिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनयन (मनोनीत) करने के लिए अधिकृत है।

Q100. Ans: C

Solution: 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 'क' के अन्तर्गत अनुच्छेद 51 (a) में जोड़ा गया।

Q101. Ans: C

Solution: अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख है।

Q102. Ans: C

Solution: राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ – साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली, पाण्डिचेरी तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

Q103. Ans: D

Solution: सभी कथन सत्य है।

अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।

Q104. Ans: A

Solution: विकल्प a सत्य नहीं है।

वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का समविश किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि माता – पिता अथवा अभिभावक 6-14 तक के आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।

Q105. Ans: A

Solution: कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी अर्ह होगा, जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है। शेष कथन सत्य है।

Q106. Ans: D

Solution: कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल का पद धारण कर (कार्यकाल पूरा कर लिया है फिर भी) लिया है उसे पुनः राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

Q107. Ans: C

Solution: किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

Q108. Ans: B

Solution: महाधिवक्ता की नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है, शेष पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

Q109. Ans: B

Solution: भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, इसमें भारत के संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण करने की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदाई था।

Q110. Ans: A

Solution: भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई अवधारणाएं हैं - सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन।

Q111. Ans: D

Solution: संविधान सभा ने 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया एवं इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गये थे। 26 नवंबर, 1949 को प्रभावी अनुच्छेद – 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 394। 26 जनवरी, 1950 को सम्पूर्ण संविधान लागू किया गया था।

Q112. Ans: D

Solution: उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था एवं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था इन राज्यों में – बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम शामिल हैं। इन राज्यों में विधान सभा एवं विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।

Q113. Ans: B

Solution: डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जो निम्नलिखित थे – डॉ. भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष), एन. गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी. एल. मित्र एवं डी. पी. खेतान। इसमें बाद में, बी. एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के पश्चात टी. टी. कृष्णामाचारी को सम्मिलित किया गया था।

Q114. Ans: A

Solution: इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंद कर कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल दिया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था।

Q115. Ans: A

Solution: संविधान सभा की गठित समितियों में प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष निम्नलिखित थे-

- संघ शक्ति समिति – जवाहर लाल नेहरू
- संघीय संविधान समिति – जवाहर लाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति – सरदार पटेल
- प्रारूप समिति – डॉ. भीमराव अंबेडकर
- राज्यों से समझौता करने वाली समिति – जवाहर लाल नेहरू
- संचालन समिति – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति – एस. वरदाचारी

Q116. Ans: D

Solution: न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को 'संविधान की मूल आत्मा' कहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)' को संविधान की आत्मा कहा है। के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के लिए कहा है – 'संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है।'

Q117. Ans: A

Solution: जनता के लिए कुछ खास सुधार न करके सांप्रदायिकता

को वैधानिकता प्रदान करने के कारण भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 के प्रावधानों को 'हितैषी निरंकुशवाद' या 'संवैधानिक तानाशाही' का नाम दिया गया था।

Q118. Ans: C

Solution: चार्टर एक्ट, 1833 के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ई. में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

Q119. Ans: D

Solution: संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना, गैर-न्यायिक है अर्थात् इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Q120. Ans: D

Solution: भारतीय संसद की संप्रभु स्थिति संविधान के उपबंधों के अधीन है। संविधान ही भारतीय संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत संसद केवल उन विषयों के संबंध में कानून बना सकती है जो या तो संघ सूची में हैं अथवा समवर्ती सूची में। संसद द्वारा बनाए गए कानून उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन भी होते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है।

Q121. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान में एकात्मता के लक्षण निम्नलिखित हैं- एकल नागरिकता का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति, संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान एवं राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए एवं संविधान की व्याख्या हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है जो कि एक संघीय व्यवस्था की विशेषता है।

Q122. Ans: D

Solution: उपर्युक्त तीनों विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने का प्रावधान कनाडा के संविधान से एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है।

Q123. Ans: D

Solution: भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22

जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है प्रस्तावना को केवल एक बार 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था।

Q124. Ans: C

Solution: विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा की जाती है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।

विधान परिषद चुनाव में सदस्यों का निर्वाचन-

1/3 विधानसभा द्वारा

1/3 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा

1/12 स्नातकों द्वारा

1/12 शिक्षकों द्वारा

1/6 राष्ट्रपति द्वारा

Q125. Ans: A

Solution: विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है जबकि अविश्वास व निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

Q126. Ans: D

Solution: संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह/परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।

Q127. Ans: D

Solution: सभी कथन सत्य है।

प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य भूमिका में होता है। मंत्रि परिषद भी व्यवहारिक रूप से इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति भी मुख्य पदाधिकारियों में अधिकांश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है।

Q128. Ans: C

Solution: विकल्प c सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया - राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं परंतु इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होकर अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाते हुए महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव

पारित होने की तिथि से हटा दिया जाता है।

Q129. Ans: B

Solution: संविधान के किस अनुच्छेद में 'राज्य का महाधिवक्ता' पद का प्रावधान है जो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए।

Q130. Ans: D

Solution: दिए गए कथनों में कोई भी सत्य कथन नहीं है।

वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है।

विधान परिषद के सभापति विधानपरिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

विधानपरिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

Q131. Ans: D

Solution: राज्य विधान परिषद, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है।

Q132. Ans: B

Solution: अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित अन्य प्रावधान हैं- समवर्ती सूची एवं व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्यों के लिए निरहर्ताओं की व्याख्या है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् बजट का उल्लेख है और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है।

Q133. Ans: A

Solution: विकल्प A में दिया गया अधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाला विशेषाधिकार है। इसके अनुसार किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष व सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

Q134. Ans: B

Solution: अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। इस प्रकार 1 वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और दोनों

बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
सामान्यतः वर्ष में संसद के अधोलिखित 3 सत्र होते हैं यथा:

- ★ बजट सत्र (फरवरी से मई)
- ★ मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर)
- ★ शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)

अतः ग्रीष्मकालीन सत्र जैसा कोई सत्र नहीं होता।

Q135. Ans: C

Solution: मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। वह तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदाई होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

Q136. Ans: C

Solution: संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ शासित प्रदेशों में अपनी शक्ति का प्रयोग करके विधान मंडल की स्थापना कर सकता है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। केंद्रशासित प्रदेश के पास विधान परिषद या उच्च सदन नहीं होता है। इन्हें आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। केंद्रशासित प्रदेश में विधायिका के साथ अंतिम निर्णय केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल पर निर्भर है। पुडुचेरी भारत में एक विधान सभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है।

Q137. Ans: D

Solution: राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम से किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्य होते हैं। राज्य के कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। मुख्यमंत्री जिन राज्यों में विधान परिषद है, उस सदन (विधान परिषद) का भी सदस्य हो सकता है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता है।

Q138. Ans: D

Solution: दिए गए तीनों परिस्थितियों में किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान वर्ष 1985 में दल-बदल कानून के तहत 52 वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके माध्यम से दल-बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि दल-बदल के आधार पर निरहर्ता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

Q139. Ans: A

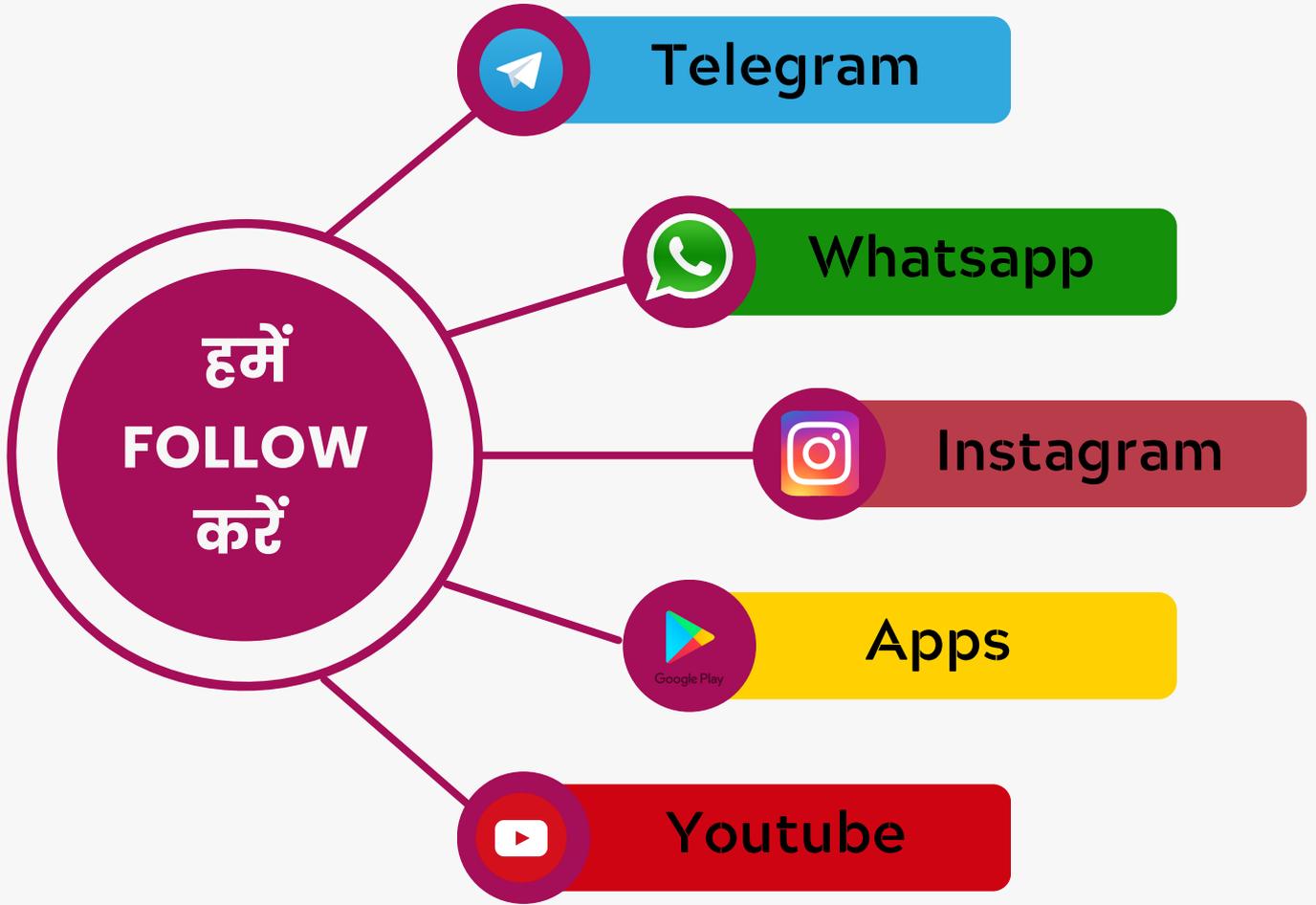
Solution: कोई संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव लाकर वाद-विवाद समाप्त करने का प्रयास करता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद-विवाद रोककर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सामान्यतः चार प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं-

- ★ साधारण कटौती
- ★ घटकों में कटौती
- ★ कंगारू कटौती
- ★ गिलोटिन प्रस्ताव

Q140. Ans: B

Solution: पंजाब राज्य को लोकसभा में कुल 13 सीट आवंटित हैं। शेष अन्य युग्म सुमेलित हैं।

Daily Current Affairs PDF, Best Test Series, Best GK PDF के लिए हमें Follow करें



 GK Trick By Nitin Gupta
The Ultimate Key to Success.

Welcome To

GK TRICK BY NITIN GUPTA APP

यहाँ पर आपको मिलेगा

- ✓ Best PDF Notes For All Exams
- ✓ Best Test Series For All Exams
- ✓ Daily Current Affairs PDF
- ✓ सभी Course बहुत ही कम Price पर
- ✓ सभी Test Detail Discription के साथ व Analysis करने को सुविधा

